

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलेक्टर, टोंक
(आर०सी० डेनवाल , आई०ए०एस० द्वारा अध्यासित)

क्र. संख्या
प्रविष्टि दिनांक

64 / 2019
16-9-2019

लोकेश सिंह मीना, अध्यक्ष आदर्श सरस्वती महिला शिक्षा एवं ग्रामीण विकास समिति प्लाट नं०-5
एच०एच० कालोनी बमोर रोड-टोंक

-अपीलाण्ट

बनाम

- 1-मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद टोंक
- 2-सहायक लेखा अधिकारी ग्रेड-॥ ग्रामीण प्रकोष्ठ, टोंक
- 3-अधिकाधी अभियन्ता अभियांत्रिकी जिला परिषद टोंक
- 4-परियोजना अधिकारी लेखा जिलापरिषद ग्रामीण वि. प्रो. टोंक

-रेस्पोडेण्ट्स

राजस्थान लोक उपायन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 के अधीन प्रारूपसं० 1
नियम 83 के तहत प्रथम अपील

उपरिस्थिति :

- (1) श्री वसन्त कुमार जैन एडवोकेट - अपीलान्ट
- (2) श्री मुरारी लाल मीना, अधिकाधी अभियन्ता अभियांत्रिकी, जिला परिषद टोंक-रेस्पोडेण्ट्स
- (3) श्री नन्द किशोर वैरवा, परियोजना अधिकारी लेखा, जिला परिषद टोंक-रेस्पोडेण्ट्स
- (4) श्री लक्ष्मीनारायण कोली, सहायक लेखा अधिकारी ग्रेड-॥, जिला परिषद टोंक-रेस्पोडेण्ट्स


निर्णय

दिनांक 16-9-2019

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अपीलार्थी संस्था द्वारा ऑनलाईन टेण्डर डाक्यूमेंट भरे गये थे जिसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद टोंक द्वारा अपीलार्थी की संस्था को अनुभवनहीन मानते हुए अपीलार्थी की फर्म का फार्म पर मुल्यांकन में अनुभव शून्य मानते हुए सलेक्शन नहीं किया गया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद टोंक के आदेश लेखा/2019-20/353 दिनांक 9-8-2019 से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद टोंक की पत्रावली तलब कर रिपोर्ट प्राप्त की गई तथा अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।




जिला कलेक्टर
टोंक

विद्वान् अभिभाषक अपीलान्त ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए ध्यान किया कि अपीलार्थी संस्था ने मैसन ट्रेनिंग करवाने वास्ते टेण्डर ऑन लाईन भरा गया था जिसमें नियमानुसार सम्पूर्ण दस्तावेज ऑनलाईन संलग्न किये गये थे लेकिन मुल्यांकन कमेटी के सदस्यगण रेस्पोजेण्ड्स द्वारा जाँच के समय फोटो कॉपी साफ नजर नहीं आने का कारण या त्रुटिवश कुछ वर्क आर्डर एवं अनुभव प्रमाण पत्र देखने से अपीलार्थी को वंचित कर दिया है, जिस कारण अपीलार्थी की संस्था को टेक्निकल पास नहीं किया गया है तथा जिस कम्पनी ओर संस्था को पास किया जा रहा है वह राजस्थान की नहीं है तथा उनका टॉक जिले में कोई ट्रेनिंग सेंटर आफिस भी नहीं है। भास्कर फाउन्डेशन का CSDCI से रजिस्ट्रेशन ही 30-3-2019 को हुआ है यानि 4 माह पहले हुआ है तो तीन साल पहले का अनुभव कहाँ से मान लिया गया। अगर माना गया है तो सही नहीं है अर्थात् भास्कर फाउन्डेशन द्वारा लगाये गये अनुभव आर्डर ही संदेहजनक है। इस कारण भी अपीलार्थी संस्था द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। अपीलार्थी संस्था द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी टॉक के आदेशानुसार मैसन ट्रेनिंग का कार्य वर्ष 2008 से 2012 तक टॉक, दौसा, अलवर में कार्य करने का अनुभव है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

Sr. No.	Work Order No./Date	Department Name	Page No	No. of Trainees
1.	F(18) TCS 1201-1239 Dated 13.06.2008	Chief Officer Tonk	232, 307, 308, 309	225
2.	F(29) TSC 09-10-371 Dated 09.07.2019	Chief Officer Tonk	233	225
3.	Shree A.K. Construction 2/3/2016	Shree A.K. Construction	302, 304	300
4.	F(29) TCS 2164/2180 Dated 01.08.2008	Chief Officer Tonk	234	255
5.	TCS /596-610 Dated 19.08.2009	Chief Officer Tonk	235	255
6.	TCS /919/929 Dated 24.09.2009	Chief Officer Tonk	236	255
7.	TCS /7088-7116 Dated 27.03.2006	Chief Officer Alwar	238	300
8.	TCS /7088-7116 Dated 31.08.2009	Chief Officer Dausa	220-221	150
9.	Saraswati Niwai Dated 30/12/2008 DGET 6/20/49/2006-TC	DGET India Govt	288, 290	2772
10.	Shiv ITI Dated 28.2.2008 DGET 6/20/49/2006-TC	DGET India Govt	289	1134
11.	Saraswati ITI Malpura Dated 30/12/2008 DGET 6/20/49/2006-TC	DGET India Govt	291	756
12.	M/s Kailash Dated 25/12/2014 to	M/s Kailash	295	250



4
जिला कलेक्टर
टोंक

	14/01/2019 Tonk			
13.	Banwari Lal Govind Prasad Dated 25/06/2015 to 2019	Banwari Lal Govind Prasad	299	250
14.	M.K. Construction Dated 20/06/2015 to 2019	M.K. Construction	305	250
15.	SWRPD – 3534 Dated 09/09/2013	Chief Engineer Water Resources Department	148-169	542
16.	PWD-215 Dated 14/05/2018	Chief Engineer (PPP) PWD	170-174	

अपीलार्थी की संस्था पिछले 25 वर्षों से कार्य कर रही है संस्था का टर्नओवर प्रतिवर्ष 14 करोड़ रुपये हैं तथा संस्था के पास टोंक जिले में टोंक, निवाई, मालपुरा, उनियारा देवली, पीपलू एवं समस्त ब्लॉक में आईटीआई कॉलेज एवं ट्रेनिंग सेन्टर 10 वर्षों से संचालित हो रहे हैं तथा समस्त भवन एवं सांजो सामान, मानव संसाधन उपलब्ध हैं। अपीलार्थी की संस्था CSDCI, एवं DGET से मान्यता प्राप्त है तथा संस्था द्वारा मेशन ट्रेनिंग करने का राजकीय अनुभव जिला परिषद टोंक, दौसा, अलवर जिला एवं आईडब्ल्यूआर एमराज्य जल संसाधन विभाग के आदेशानुसार हैं। जिला नागोर पाली आदि में भी हमारी संस्था ने मेशन ट्रेनिंग देने का कार्य सफलतापूर्वक किया है जिनका वर्क आर्डर भी ऑन लाईन टेण्डर के दौरान लगाया गया है, जिनके भी नम्बर नहीं दिये गये इस कारण अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अपीलार्थी संस्था ने प्राईवेट लि० कम्पनियों एवं फर्मों में कार्यरत अकुशल कारीगरों को प्रशिक्षण देकर कौशलपूर्ण बनाया है जिनके प्रमाण-पत्र भी ऑनलाईन टेण्डर में संलग्न हैं। जिनके भी नम्बर नहीं दिये गये इस कारण भी आलोच्य आदेश निरस्त कर अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अपीलार्थी द्वारा ऑन लाईन टेण्डर भरते वक्त मूल वर्क आर्डर ही ऑनलाईन किये थे क्योंकि टीयूआर एवं अनुबन्ध की प्रतियाँ लगाने से पृष्ठ अधिक हो रहे थे यानि फाईल काफी मोटी हो गई थी, इस कारण ऑन लाईन अपलोड नहीं हो रहा था इस कारण अपीलार्थी शेष प्रतियाँ अपील के साथ संलग्न प्रस्तुत कर रहा है। सरकार की मंशा एवं टेण्डर में अंकित पैरा के अनुसार राजस्थान राज्य की रजिस्टर्ड एवं स्थानीय संस्था को प्राथमिकता देने का उल्लेख है। अतः अपीलार्थी संस्था टोंक जिले की स्थानीय संस्था है और टेण्डर गाईड लाईन के अनुसार सम्पूर्ण अनुभव रखती है किन्तु इन तथ्यों पर रेस्पोंडेण्ट्स द्वारा कोई गौर नहीं कर भारी विधिक त्रुटि की है, इस कारण भी रेस्पोंडेण्ट्स द्वारा जारी आदेश निरस्त फरमाया जाकर सरकार की मंशा एवं टेण्डर में अंकित पैरा के अनुसार अपीलार्थी फर्म के टेण्डर फार्म का पुनः अवलोकन करने के आदेश फरमाये जावें।

अपीलार्थी के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए रेस्पोंडेण्ट्स अधिकारीगण ने तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया एवं तर्क दिया कि 25 वर्ष के अनुभव का इस निविदा के तकनीकी मापदंडों से कोई संबंध नहीं है। निविदा के लिए संस्था का CSDCI पंजीकरण होना एवं मूल्यांकन मानकों के अनुसार तीन साल का मैसन प्रशिक्षण का अनुभव होना चाहिए। फोटोकॉपी साफ नजर नहीं आने के कारण या त्रुटिवश कुछ वर्क आर्डर एवं अनुभव प्रमाण-पत्र नहीं देखने के कारण अपीलार्थी को तकनीकी रूप से वंचित नहीं किया गया है।



✍
जिला कलेक्टर
टोंक

निविदा में सफल संस्था भास्कर फाउंडेशन का जयपुर में कार्यालय है, जिसका उल्लेख संस्था द्वारा निविदा प्रपत्र में किया है। संस्था के पूर्व के रजिस्ट्रेशन की जानकारी बाबत कार्यालय जिला परिषद टोंक के पत्र क्रमांक 374 दिनांक 26.08.2019 द्वारा लिखा गया। जिसके क्रम में संस्था द्वारा अपने वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक के CSDCI पंजीकरण के प्रमाण पत्र की प्रति उपलब्ध करवा दी गयी है। अपीलार्थी फर्म द्वारा उपलब्ध करवाये गये सभी राजकीय संस्थानों के अनुभव 03 वर्ष से पूर्व के है एवं ना ही उल्लेखित कार्यादेशों में मैसन प्रशिक्षण का उल्लेख है। निविदा में मूल्यांकन में पिछले तीन वर्षों के अनुभव पर अंक प्रदान किये जाने थे। अतः फर्म को अंक नहीं देकर, तकनीकी रूप से सफल नहीं माना है। बहस के दौरान अपीलार्थी संस्था द्वारा भी माना गया कि उसको पिछले तीन वर्षों में मैसन से संबंधित राजकीय कार्य का अनुभव नहीं है एवं ना ही उसके द्वारा इसके प्रमाण पत्र निविदा के साथ अपलोड किये है।

अपीलार्थी संस्था द्वारा CSDCI पंजीकरण की अस्पष्ट प्रति निविदा प्रपत्र के साथ उपलब्ध करवायी है। संस्था से कार्यालय जिला परिषद टोंक के पत्र क्रमांक 377 दिनांक 26.08.2019 एवं पत्र क्रमांक 386 दिनांक 27.08.2019 द्वारा दिनांक 29.08.2019 शाम 6.00 बजे तक अपनी संस्था के रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्रों की प्रति उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया था। उक्त पत्रों को संस्था को जरिये रजिस्टर्ड डाक, ई-मेल, वाट्स एप द्वारा भिजवाया गया है एवं दूरभाष पर भी इसकी सूचना दी गयी है। परन्तु संस्था द्वारा आदिनांक तक इस बारे में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाये है। बहस के दौरान भी अपीलार्थी संस्था से CSDCI पंजीकरण की प्रति मांगी गयी परन्तु संस्था द्वारा तब भी पंजीकरण की प्रति उपलब्ध नहीं करवायी गयी। निविदा के साथ संलग्न दस्तावेजों में मैसन प्रशिक्षण का कोई उल्लेख नहीं है। एवं संलग्न दस्तावेज भी पिछले तीन वर्षों से संबंधित नहीं है। जो कि निविदा के मूल्यांकन के तकनीकी मापदंडों के अनुरूप नहीं है। प्राईवेट लिमिटेड कंपनियों एवं फर्मों के प्रमाण पत्रों को इस निविदा में उपापन समिति द्वारा मान्य नहीं किया गया है क्योंकि यह कंपनियाँ एवं फर्म द्वारा दिये गये प्रशिक्षण CSDCI के मानकों के अनुरूप नहीं होते हैं। निविदा के साथ संलग्न दस्तावेजों में किसी में भी मैसन प्रशिक्षण का उल्लेख नहीं था। एवं दूसरी संस्था द्वारा कम पृष्ठों पर मैसन प्रशिक्षण के अन्य राज्य सरकारों के दस्तावेज मय कार्यादेशों के उपलब्ध करवाये है। साथ ही संस्था द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न Tech-3B की प्रति भी रिक्त ही संलग्न की है, जिसमें कि निविदा मूल्यांकन संबंधी विवरण अंकित किया जाना था एवं यह निविदा प्रपत्र के साथ आवश्यक थी। Tech-3B की सूचना के आधार पर तकनीकी मूल्यांकन किया जाना था। निविदा प्रपत्र के परिशिष्ट-4 के अनुसार संस्था का राजस्थान की भौगोलिक सीमा में कार्यालय होना चाहिए। निविदा में सफल संस्था का जयपुर में कार्यालय है, जिसके बारे में संस्था द्वारा अपने निविदा प्रपत्र में उल्लेख किया गया है।

हमने उभयपक्षों की बहस को सुना एवं पत्रावली पर आये दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। पत्रावली एवं प्रस्तुत तथ्यात्मक प्रतिवेदन/जवाब के अवलोकन से निविदा तकनीकी रूप से निरस्त किये जाने के सभी कारणों को अपलोड किये गये दस्तावेजों से सत्यापित पाया गया। तकनीकी निविदा प्रपत्र एवं उसके साथ संलग्न दस्तावेजों को अपीलार्थी संस्था द्वारा पूर्ण रूप से उचित प्रारूप में भरकर प्रस्तुत नहीं किया गया एवं ना ही निविदा के साथ चाहे गये सम्पूर्ण दस्तावेज अपलोड किये। मैसन प्रशिक्षण से संबंधित उक्त निविदा के लिए तकनीकी रूप से सफल होने का मुख्य आधार संस्था का CSDCI से मान्यता /रजिस्टर्ड होना एवं पिछले तीन वर्षों का मैसन प्रशिक्षण का अनुभव होना था। अपीलार्थी फर्म द्वारा निविदा प्रपत्र




जिला कलेक्टर
टोंक

के साथ CSDCI से मान्यता /रजिस्ट्रेशन की अस्पष्ट प्रति संलग्न की थी एवं जिला परिषद कार्यालय के पत्रांक एवं बहस के दौरान उक्त प्रमाण पत्र अपनी मान्यता के स्पष्ट दस्तावेज/रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं करवाये गये। आज निर्णय दिनांक 16.09.2019 को संस्था द्वारा निविदा से संबंधित अनुभव एवं निविदा के साथ अपलोड किये जाने वाले कुछ दस्तावेजों की छाया प्रतियाँ प्रस्तुत की हैं जिसे निविदा के साथ ही अपलोड किया जाना अपेक्षित था जो नियमानुसार अब प्रस्तुत किया जाना उचित नहीं है। निविदा मूल्यांकन के लिए मुख्य आधार निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न Tech-3B को भी अपीलार्थी संस्था द्वारा रिक्त ही निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न किया गया है। अपीलार्थी फर्म द्वारा निविदा प्रपत्र के संलग्न दस्तावेजों में संलग्न कार्यादेश में किसी में भी मैसन प्रशिक्षण का उल्लेख नहीं है एवं ना ही पिछले तीन वर्षों में मैसन प्रशिक्षण से संबंधित राजकीय कार्य के अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये हैं।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद टोंक के पत्र क्रमांक 185 दिनांक 10.07.2019 द्वारा जारी निविदा में पत्र क्रमांक 353 दिनांक 09.08.2019 द्वारा निविदा देने एवं अनुबंध के संबंध में की गयी कार्यवाही नियमानुसार उचित एवं न्याय संगत प्रतीत होती है। अतः अपील अपीलान्त खारिज की जाती है।




(आर0सी0 डेनवाल)
जिला कलेक्टर टोंक
टोंक